

04/04/2024

## शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. सुप्रीम कोर्ट मतदान से पहले ईवीएम में गिनती की पुष्टि पर याचिकाएं सूचीबद्ध करेगा ( GS PAPER II: चुनाव सुधार)
2. परमाणु ऊर्जा भारत के विकास की कुंजी है ( GS PAPER III: पर्यावरण)
3. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष ( एनडीआरएफ) (GS PAPER III: आपदा प्रबंधन)
4. शहरी गरीबों पर प्रकाश डालना ( GS PAPER III: रोजगार)
5. राजकोषीय लड़ाई: उधारी और केरल के मुकदमे पर ( GS PAPER II: केंद्र - राज्य संबंध)
6. बेहतर भविष्य के लिए सिस्टम विज्ञान ( निबंध)
7. भारत में लिविंग विल्स कार्यान्वयन में देरी ( GS PAPER II: डाई विद डिग्रीटी)

## राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष ( एनडीआरएफ) (GS PAPER III: आपदा प्रबंधन)

- एनडीआरएफ प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है।
- उद्देश्य: यह आपदाओं के बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- स्थापित: पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NDRF) के रूप में जाना जाता था, 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम (धारा 46) के तहत इसका नाम बदल दिया गया।
- फंडिंग: फंड में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है, राज्य सरकारों या सार्वजनिक दान जैसे अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान की अनुमति होती है।
- राज्य निधि का पूरक: एनडीआरएफ राज्यों के लिए एक पूरक स्रोत के रूप में कार्य करता है जब उनका अपना राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) बड़े पैमाने पर आपदा के लिए अपर्याप्त होता है।

# भारत के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा परिदृश्य परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है: रिपोर्ट

आईआईएम-ए के अध्ययन में कहा गया है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की राह पर चलना है तो उसे इस ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी और संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्तार करना होगा।

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा वित्त पोषित भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के शिक्षाविदों द्वारा किया गया एक अध्ययन, 2047 तक विकसित स्थिति और शुद्ध शून्य हासिल करने के लिए भारत के लिए परमाणु ऊर्जा और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता देने का सुझाव देता है। 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन।
- वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा में भारत के ऊर्जा मिश्रण का केवल 1.6% हिस्सा शामिल है।
- अध्ययन उच्च, मध्यम और निम्न आर्थिक विकास सहित विभिन्न परिदृश्यों की पड़ताल करता है, और ऊर्जा स्रोतों पर अलग-अलग ध्यान केंद्रित करता है: परमाणु ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और भंडारण के साथ जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन), और इन सभी का संयोजन।
- 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2030 और 2050 तक आवश्यक ऊर्जा मिश्रण का अनुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया गया था, जिसमें भारत की जनसंख्या द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों के बराबर मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने और ऊर्जा पहुंच की घटती लागत जैसे कारकों पर विचार किया गया था।
- सबसे अनुकूल परिदृश्य में उत्सर्जन 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने का अनुमान है, परमाणु ऊर्जा मौजूदा स्तर से पांच गुना बढ़कर 2030 तक 30 गीगावॉट और 2050 तक 265 गीगावॉट हो जाएगी।
- इस परिदृश्य में, भारत की कुल ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का योगदान 2030 में 4% से बढ़कर 2050 तक 30% होने का अनुमान है, जबकि सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 2030 में 42% से घटकर 2050 में 30% हो जाएगी।

## यूरेनियम उपलब्धता

- सौर ऊर्जा वर्तमान में भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता का 16% प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कोयले की हिस्सेदारी 49% है।
- परमाणु ऊर्जा के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए निवेश को दोगुना करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध द्वारा प्रतिबंधित महत्वपूर्ण ईंधन यूरेनियम की आवश्यक मात्रा में **उपलब्धता की आवश्यकता होगी।**
- आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर और अध्ययन के मुख्य लेखक अमित गर्ग के अनुसार, भारत के ऊर्जा मिश्रण में विभिन्न प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर बल देते हुए, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कोई एकल समाधान ("सिल्वर बुलेट") नहीं है।
- उम्मीद है कि कोयला भारत की ऊर्जा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक ("रीढ़ की हड्डी") बना रहेगा। यदि देश का लक्ष्य अगले तीन दशकों के भीतर कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है,

तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन करने के लिए लचीले ग्रिड बुनियादी ढांचे और भंडारण के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों में निवेश करने की आवश्यकता होगी।

- रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में परिवर्तन के लिए 2020-2070 के बीच ₹150-200 लाख करोड़ के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी।

## चंद्रमा के चारों ओर दूरबीन लगाने पर विचार कर रहे देशों में भारत भी शामिल है

- चंद्रमा पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन तैनात करने की संभावना से उत्साहित हैं और ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए इसके चारों ओर कक्षा में।
- ऐसा ही एक प्रस्ताव है प्रत्यूष, जो भारत द्वारा शुरू किया गया है।
- पृथ्वी पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप दृश्य प्रकाश एकत्र करते हैं लेकिन वायुमंडलीय हस्तक्षेप के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसमें आकाश को अस्पष्ट करने वाला प्रदूषण भी शामिल है।
- रेडियो टेलीस्कोप, जो रेडियो तरंगों का पता लगाते हैं, रेडियो और टीवी सिग्नलों के हस्तक्षेप के साथ-साथ रडार सिस्टम, विमान और उपग्रहों से विद्युत चुम्बकीय 'हिस' जैसी कठिनाइयों का भी सामना करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, पृथ्वी का आयनमंडल बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को रोकता है, जिससे अवलोकन और भी जटिल हो जाता है।

### एक प्राचीन उजाड़

- पूरे ग्रह से बढ़ते रेडियो शोर के कारण वैज्ञानिकों को पृथ्वी की कक्षा में रेडियो दूरबीनों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- पृथ्वी से दूर चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर दूरबीनें लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
- चंद्रमा का सुदूर भाग प्राचीन, वायुहीन स्थिति प्रदान करता है, जो दो सप्ताह की चंद्र रात के दौरान ऑप्टिकल दूरबीनों के लिए क्रिस्टल-स्पष्ट देखने की स्थिति प्रदान करता है।
- चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थित रेडियो दूरबीनों को चंद्रमा द्वारा ही पृथ्वी के रेडियो प्रसारण और सूर्य से आने वाली विद्युत आवेशित प्लाज़्मा हवाओं से बचाया जाएगा।
- अतीत में, उच्च लागत ने चंद्र दूरबीनों को स्थापित करने में बाधा उत्पन्न की थी, लेकिन चंद्र अन्वेषण में नई रुचि ने इसे संभव बनाने का वादा किया है।
- जैसा कि द रॉयल सोसाइटी ने कहा है, यह कदम खगोलविदों को "सौर मंडल में सबसे रेडियो-शांत स्थान" तक पहुंच प्रदान कर सकता है।

### ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्रकाश

- ब्रह्माण्ड विज्ञानियों का मानना है कि ब्रह्माण्ड की शुरुआत एक अत्यंत छोटे, घने बूँद के रूप में हुई जो एक बिग बैंग में फट गया।
- बिग बैंग के बाद, ब्रह्मांड ठंडा और विस्तारित हुआ, इसकी चकाचौंध रोशनी अंधेरे में लुप्त हो गई।
- लगभग 300,000 से आधा अरब वर्षों तक, ब्रह्मांड अंधेरे की स्थिति में था, केवल हाइड्रोजन और हीलियम के निशान थे।

- यह अंधकारमय काल ब्रह्मांडीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण चरण का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- अंधकार तब समाप्त हुआ जब पहले तारे प्रज्वलित हुए, प्रकाश उत्सर्जित किया और ब्रह्मांड का विस्तार जारी रखा।
- कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (सीएमबी), ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्रकाश, इस विस्तार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक फीकी चमक है, जिसे रेडियो दूरबीनों द्वारा पता लगाया जा सकता है।
- सीएमबी प्रकीर्णन के बाद, ब्रह्मांड ने एक "शांत" अवधि में प्रवेश किया, जिसे अंधकार युग के रूप में जाना जाता है, जो लाखों वर्षों तक चलता है।
- अंधकार युग के दौरान, गुरुत्वाकर्षण ने पहले सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू किया।
- तटस्थ हाइड्रोजन अंधकार युग के दौरान ब्रह्मांड में कुछ सीएमबी विकिरण को अवशोषित कर लिया, जिससे रेडियो तरंगों के फैलने की आवृत्ति में थोड़ी गिरावट आ गई।

## चीन फिर से पहला हो सकता है

- पृथ्वी पर मौजूद उपकरण आवृत्ति में बहुत मामूली गिरावट का पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसके बजाय चंद्रमा पर उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।
- ये चंद्रमा-आधारित उपकरण ब्रह्मांड के "अंधकार युग" के संकेतों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जब कोई तारे नहीं थे, क्योंकि वे तारों के प्रकाश के हस्तक्षेप से मुक्त हैं।
- लूनर सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट ( लूएसईई नाइट) नासा और बर्कले लैब के बीच एक संयुक्त परियोजना है, जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च करने की तैयारी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी शोर को कम करने के लिए यह पृथ्वी के विपरीत, भूमध्य रेखा के पास चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरेगा।
- नासा और ईएसए जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा चंद्रमा से जुड़े अन्य उपकरणों की भी योजना बनाई जा रही है।
- नासा का लॉन्ग-बेसलाइन ऑप्टिकल इमेजिंग इंटरफेरोमीटर चंद्रमा के दूर से सितारों और आकाशगंगाओं पर चुंबकीय गतिविधि का अध्ययन करेगा।
- ईएसए योजना 2030 तक अपने चंद्र लैंडर 'अर्गोनॉट' पर एक रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च करने के लिए।
- यूरोपीय परियोजनाओं में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के लिए डिटेक्टर और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक छायादार क्रेटर में एक अवरक्त दूरबीन शामिल है।
- चीन 2026 में लॉन्च होने वाले चंद्रमा-परिक्रमा रेडियो टेलीस्कोप में भी शामिल है।
- चीन का व्यूकियाओ-2 उपग्रह, जिसमें 4.2-मीटर एंटीना शामिल है, संभवतः 24 मार्च को चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया गया था, जो संचार रिले और रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेगा।

## प्रत्यूष रेडियो दूरबीन

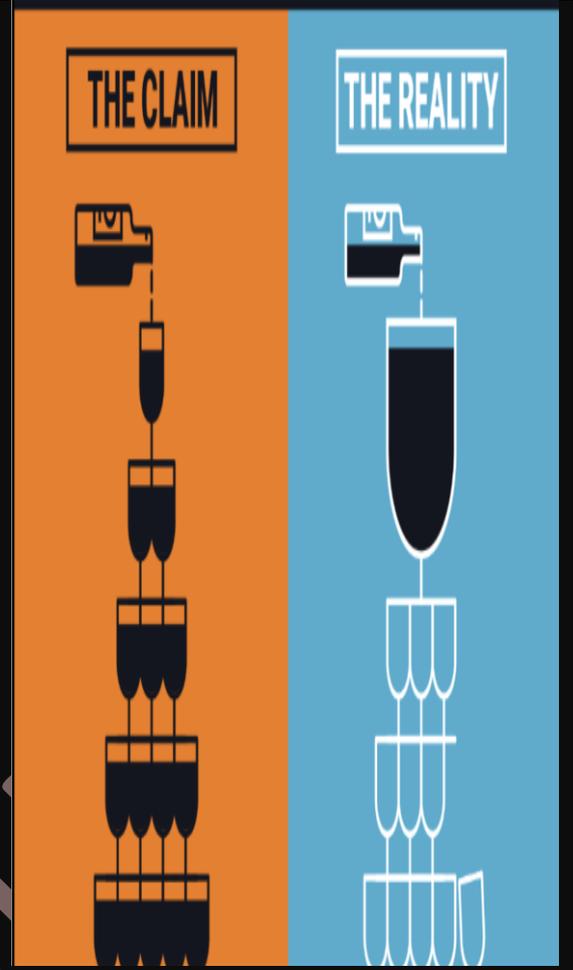
- चंद्रमा की सतह पर उपकरणों को तैनात करना मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिक इसके बजाय चंद्रमा के चारों ओर उपग्रहों की परिक्रमा करने पर विचार कर रहे हैं।
- डॉ. सुजुकी चंद्रमा की परिक्रमा करने और उपग्रह के पीछे होने पर डेटा का अध्ययन करने के लिए इस वैकल्पिक दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं।

- चंद्रमा के दूर से ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप PRATUSH ( हाइड्रोजन से सिग्नल का उपयोग करके ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण की जांच) के साथ इस विधि का उपयोग करने की योजना बनाई है।
- PRATUSH का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सहयोग से बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) द्वारा किया जा रहा है।
- प्रारंभ में, इसरो चंद्रमा की ओर प्रक्षेपित करने से पहले प्रत्यूष को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा।
- पृथ्वी की कक्षा में संचालन में रेडियो फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप (आरएफआई) होगा, लेकिन यह जमीन-आधारित प्रयोगों पर लाभ प्रदान करता है, जैसे कि मुक्त स्थान में संचालन और आयनमंडल से कम प्रभाव।
- एक बार चंद्रमा की कक्षा में, प्रत्यूष को न्यूनतम आरएफआई और बिना आयनमंडल के आदर्श अवलोकन स्थितियों का अनुभव होगा।
- अंधकार युग के रेडियो संकेतों का अध्ययन करने के लिए एक वाइडबैंड एंटीना, सेल्फ-कैलिब्रेटिंग एनालॉग रिसीवर और डिजिटल सहसंबंधक सहित विशेष उपकरण ले जाएगा।
- जैसे-जैसे खगोलविद चंद्रमा से ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, वे डार्क एनर्जी, आदिम ब्लैक होल और ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के बारे में नई खोजों को उजागर करने की उम्मीद करते हैं।

## शहरी गरीबों पर प्रकाश डालना ( GS PAPER III: रोजगार)

झुग्गीवासियों की आय और रोजगार के रुझान का विश्लेषण शहरी भारत में गरीबों के लिए आर्थिक गतिशीलता और अच्छे काम की संभावनाओं की ओर इशारा करता है।

- मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संचालित भारत रोजगार रिपोर्ट (IER) 2024, श्रमिक वर्ग पर आर्थिक विकास के धीरे-धीरे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताती है।
- यह 2015-16 से 2022-23 तक 5.4% औसत वास्तविक आर्थिक विकास पर प्रकाश डालता है लेकिन रोजगार और आय के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भिन्न रुझान की ओर इशारा करता है।
- 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 4.8% की उच्च बेरोजगारी दर प्रदर्शित हुई, फिर भी शहरी निवासी काफी अधिक कमाते हैं, औसत मासिक आय स्व-रोजगार के लिए 76% अधिक, नियमित कर्मचारियों के लिए 44% और 22% अधिक है। 2022 में शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक मजदूरों के लिए।



- उच्च बेरोजगारी और मजदूरी का सह-अस्तित्व शहरी गरीबों पर इसके प्रभाव की आगे की जांच को प्रेरित करता है।
- यह लेख मलिन बस्तियों जैसे गहरी शहरी गरीबी वाले क्षेत्रों में रोजगार और मजदूरी की गतिशीलता की पड़ताल करता है, और इन निष्कर्षों की तुलना IER 2024 परिणामों से करता है।
- शहरी क्षेत्रों में अधिक आय के बावजूद, ग्रामीण-शहरी प्रवासन धीमा हो गया है, जो विशेष रूप से पुरुषों के बीच आर्थिक गतिशीलता के लिए प्रवासन में गिरावट का संकेत देता है।

ग्रामीण गरीब परिवार अक्सर औपचारिक बस्तियों के बजाय मलिन बस्तियों की ओर पलायन कर जाते हैं, जिससे शहरी गरीबों के लिए आर्थिक गतिशीलता और अच्छे काम के अवसरों पर सवाल उठते हैं।



## कोलकाता में सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- लेखक और उनकी टीम ने 2012 में और फिर 2022-23 में पूरे कोलकाता में 37 मलिन बस्तियों में सर्वेक्षण किया, पुनर्विकास या बेदखली के कारण 29 मलिन बस्तियों पर नज़र रखी।
- सर्वेक्षण में 2012 में 513 झुग्गी-झोपड़ियों के परिवारों और 2021-22 में 396 परिवारों को शामिल किया गया, तुलना के लिए COVID-19-प्रभावित वर्षों से बचने के लिए 2019 में अतिरिक्त डेटा एकत्र किया गया।
- अकुशल श्रम सबसे आम व्यवसाय बना हुआ है, कामकाजी आबादी का एक चौथाई हिस्सा ऐसे काम में लगा हुआ है, जो आईईआर 2024 में पाए गए राष्ट्रीय रुझानों को दर्शाता है।
- अन्य प्रचलित व्यवसाय इसमें कुशल या अर्ध-कुशल श्रम, निजी संगठनों में रोजगार और छोटे व्यवसायों या छोटी दुकानों का स्वामित्व शामिल है।
- हालाँकि, 2012-19 के बीच कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों में रोजगार की हिस्सेदारी में 6% और निजी संगठनों में 3% की गिरावट आई है।
- इसके विपरीत, छोटे व्यवसायों या छोटी दुकानों में रोजगार में 9% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य स्व-रोज़गार की हिस्सेदारी में 3% की गिरावट आई है।
- पहले कम लोकप्रिय व्यवसायों ने पिछले दशक में गति पकड़ी है, जैसे टुक ड्राइविंग और सफाई (5% तक) और निर्माण और संबंधित कार्य (4% तक), जिनका 2012 में न्यूनतम प्रतिनिधित्व था।

## आय के रुझान

- 2012 में कोलकाता की मलिन बस्तियों में औसत मासिक आय लगभग ₹4,900 थी, जो 2019 में स्थिर कीमतों (2012) पर 5% कम हो गई।
- दोनों अवधियों में सरकारी कर्मचारियों की आय सबसे अधिक थी, लेकिन 2019 में स्थिर कीमतों पर उनकी मासिक आय 5% कम हो गई।
- घरेलू नौकरों और अकुशल श्रमिकों की आय लगातार सबसे कम रही।
- निर्माण और संबंधित कार्यों में 2012 से 2019 तक वास्तविक आय में सबसे अधिक गिरावट (51%) का अनुभव हुआ, इसके बाद छोटे व्यवसाय या छोटी दुकान (32%) और सरकारी सेवा (32%) का स्थान रहा।
- मध्यम से बड़े दुकान मालिकों को भी वास्तविक आय में 26% की हानि हुई।
- श्रम कार्य की लोकप्रियता बढ़ी, अकुशल श्रम की वास्तविक आय में 33% की वृद्धि हुई, जबकि कुशल या अर्ध-कुशल श्रम आय में 12% की वृद्धि हुई, लेकिन 2012 की तुलना में 2019 में कम रोजगार मिला।
- IER 2024 इसी तरह के रुझान को दर्शाता है, जिसमें स्व-रोज़गार व्यक्तियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन स्व-रोज़गार और नियमित श्रमिकों के लिए वास्तविक मासिक वेतन में गिरावट आई है।
- मजदूरों सहित आकस्मिक श्रमिकों की वास्तविक मासिक मजदूरी में 2012-19 के बीच ₹3,701 से ₹4,364 तक की वृद्धि देखी गई।
- सरकारी नौकरों जैसे अधिक कमाई करने वालों की आय में गिरावट के बावजूद, घरेलू नौकरों जैसे सबसे कम कमाई करने वालों की वास्तविक आय दोगुनी हो गई, जिससे मलिन बस्तियों में आय असमानता कम हो गई।

- कोलकाता की व्यवसाय श्रेणियों में लिंग संरचना में 2012 की तुलना में 2021-22 में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में 3% की गिरावट देखी गई। हालाँकि, IER 2024 में 2012-2022 के दौरान महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में 1.6% की वृद्धि देखी गई है, संभवतः गैर-स्लम क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी के कारण।

## आकस्मिक कार्य में वृद्धि

- आईईआर 2024 और सर्वेक्षण डेटा के बीच तुलना बढ़ती मजदूरी के कारण आकस्मिक श्रम, विशेष रूप से श्रम कार्य में वृद्धि का संकेत देती है।
- हालाँकि, आकस्मिक काम में अक्सर उचित कामकाजी परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा उपायों का अभाव होता है।
- स्व-रोजगार, जैसे छोटे व्यवसाय, बढ़ रहे हैं, लेकिन आय में आनुपातिक वृद्धि के बिना, झुग्गी-झोपड़ियों में बड़ी संख्या में कम कमाई वाले छोटे व्यवसाय के मालिक हैं।
- मलिन बस्तियों में महिला कार्यबल की भागीदारी शहरी क्षेत्रों में समग्र बढ़ती प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित नहीं करती है, जो रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में महिलाओं के लिए चुनौतियों का संकेत देती है।
- आय असमानता में कमी के बावजूद, समग्र आय स्तर में गिरावट आई, जिससे शहरी गरीब और अधिक गरीबी में चले गए।
- उच्च आय शहरी गरीबों के लिए बेहतर आर्थिक गतिशीलता और नौकरी की गुणवत्ता में तब्दील नहीं होती है।
- किफायती भोजन और लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में अधिक सार्वजनिक समर्थन की आवश्यकता है।
- 2000-08 और 2021 के दौरान पुरुष प्रवासन में गिरावट को कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्रों में धीमी वृद्धि के साथ-साथ नकारात्मक रोजगार वृद्धि जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को उजागर करता है।

## राजकोषीय लड़ाई: उधारी और केरल के मुकदमे पर (GS PAPER II: केंद्र -राज्य संबंध)

केरल का मुकदमा राज्यों के उधार लेने के अधिकार और इसे सीमित करने की केंद्र की शक्ति पर सवाल उठाता है

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी उधारी पर केंद्र के फैसले के संबंध में केरल द्वारा दायर एक मुकदमे को संविधान पीठ के पास भेज दिया।
- न्यायालय ने केरल की उधार स्थिति को बहाल करने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य की उधारी को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार की सीमा की जांच करने का विकल्प चुना।
- इस मामले में केरल के वाम मोर्चा शासन के खिलाफ राजकोषीय कुप्रबंधन के आरोपों से कहीं अधिक शामिल है; यह केंद्र-राज्य संबंधों पर संवैधानिक प्रश्नों के बारे में है।

- विवाद के मूल में **अनुच्छेद 293** है, जो राज्यों को आगे के ऋण के लिए संघ की सहमति से, उनकी विधायिका द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार लेने का अधिकार देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 भारत के भीतर राज्यों की उधार लेने की शक्तियों से संबंधित है।

1. **राज्यों की उधार लेने की कार्यकारी शक्ति** : इस लेख में कहा गया है कि किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उसे राज्य की समेकित निधि को सुरक्षा के रूप में उपयोग करके भारत के भीतर धन उधार लेने की अनुमति देती है। हालाँकि, यह उधार राज्य विधानमंडल द्वारा कानूनों के माध्यम से निर्धारित सीमाओं के अधीन है। इसके अतिरिक्त, राज्य इन सीमाओं के भीतर ऋण के लिए गारंटी प्रदान कर सकते हैं।
2. **भारत सरकार की भूमिका** : केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास राज्यों को धन उधार देने या राज्यों द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करने का अधिकार है, जब तक कि संसद द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें पूरी होती हैं। ऐसे ऋणों के लिए आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि से ली जाती है।
3. **सहमति की आवश्यकता** : कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना ऋण नहीं उठा सकता है यदि केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य को पहले दिए गए ऋणों का कुछ हिस्सा बकाया है या जिसके लिए गारंटी प्रदान की गई है। यह राज्य और केंद्रीय वित्त के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करता है।
4. **सहमति के लिए शर्तें** : यदि भारत सरकार किसी राज्य को ऋण जुटाने के लिए सहमति देती है, तो वह आवश्यक समझे जाने पर कुछ शर्तें लगा सकती है।

- 'नेट बॉरोइंग सीलिंग' में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार और अपने सार्वजनिक खाते पर देनदारियों को शामिल करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है।
- केंद्र सरकार ने 2018 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करके 'सामान्य सरकारी ऋण' को जीडीपी के 60% तक सीमित कर दिया, जिसका उद्देश्य ऑफ-बजट उधार को रोकना था।
- केरल का तर्क है कि राज्य सरकार की असीमित उधारी से उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी और निजी क्षेत्र के उधारकर्ता बाहर हो जाएंगे।
- केरल का संकट राजस्व वितरण और राजकोषीय स्थिति के बारे में चिंताओं को उजागर करता है, विशेष रूप से केरल जैसे सामाजिक संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए।
- राजस्व स्रोत जीएसटी-साझाकरण प्रणाली में स्थानांतरित होने के साथ, राजकोषीय स्थान महत्वपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट उधार सीमा पर केंद्र की सख्ती और संघीय मानदंडों को कायम रखने के बीच संतुलन का निर्धारण करेगा।

## मुख्य अभ्यास प्रश्न

**सवाल:** भारत के 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम बनाया है? (150 शब्द/10 अंक) (यूपीएससी 2021)

### उत्तर दृष्टिकोण

- भारत के वित्त आयोग और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका को संक्षेप में परिभाषित करते हुए उत्तर का परिचय दें।
- फिर 14वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों की रूपरेखा प्रस्तुत करें, विशेष रूप से वे सिफारिशें जो राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित हैं।
- आगे बताएं कि कैसे प्रत्येक सिफारिश ने सीधे राजस्व, स्वायत्तता, जिम्मेदारी और प्रदर्शन को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों के लिए वित्तीय स्वास्थ्य में वृद्धि हुई।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति को कैसे मजबूत किया, इसका सारांश देते हुए निष्कर्ष निकालें।

## उत्तर

**भारत का वित्त आयोग** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। हर पांच साल में यह केंद्र (केंद्र सरकार) और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। किसी राज्य का वित्तीय स्वास्थ्य, जिसमें राजस्व, व्यय, ऋण और समग्र वित्तीय स्थिरता शामिल है।

### 14वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- **कर हिस्सेदारी का बढ़ा हुआ हस्तांतरण:**
  - केंद्र के करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को **32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया**, जिससे राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- **सहायता अनुदान:**
  - राज्यों को अनुदान को तर्कसंगत बनाया गया, विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए लक्षित सहायता प्रदान की गई, साथ ही राज्यों के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई।
  - प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन अनुदान की शुरुआत की गई।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का पुनर्गठन:**
  - सीएसएस की संख्या कम कर दी गई, जिससे राज्यों को विकास कार्यक्रमों को लागू करने में अधिक लचीलापन मिल गया।
  - केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त निधियों का हिस्सा बढ़ाया गया।

### सिफारिशों से राज्यों की राजकोषीय स्थिति में कैसे सुधार हुआ

- **बढ़ा हुआ राजस्व:** करों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी ने राज्यों के उपलब्ध संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे उनके बजट में वृद्धि हुई।
- **अधिक राजकोषीय स्वायत्तता:** राज्यों को संसाधन आवंटन और व्यय निर्णयों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ, जिससे धन के कुशल और अनुरूप उपयोग को बढ़ावा मिला।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व:** केंद्रीय अनुदान पर कम निर्भरता और बढ़ते हस्तांतरण ने राज्यों को राजस्व सृजन और व्यय प्रबंधन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **प्रदर्शन पर ध्यान:** अनुदान के भीतर प्रोत्साहन संरचनाओं ने राज्यों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना:** आयोग ने अपनी सिफारिशों में पिछड़ेपन और राजकोषीय जरूरतों जैसे कारकों पर विचार किया, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच समान अवसर प्रदान करना था।

इस प्रकार, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी बढ़ाकर, निर्बाध अनुदान प्रदान करके और विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करके, आयोग ने राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा दिया है और राज्यों को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सशक्त बनाया है। हालाँकि, शेष चुनौतियों का समाधान करने और राज्यों में सतत विकास के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

### इस उत्तर को लिखने का दूसरा तरीका

वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय कर राजस्व की हिस्सेदारी में इस वृद्धि ने राज्यों को एक बड़ा राजस्व आधार प्रदान किया है, जिससे उनकी राजकोषीय क्षमता में वृद्धि हुई है।

### प्रमुख सिफारिशें और उनका प्रभाव

- अपने पास अधिक संसाधनों के साथ, राज्य विकासात्मक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू करने और गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हैं।

- आयोग ने केंद्रीय निधियों का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को अनटाइड अनुदान के रूप में हस्तांतरित करने की वकालत की।
- बंधी अनुदान से अनटाइड फंड की ओर इस बदलाव ने राज्यों को संसाधन आवंटन में अधिक लचीलापन प्रदान किया है, जिससे उन्हें अपनी विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताओं और जरूरतों के आधार पर धन आवंटित करने की अनुमति मिली है।
- परिणामस्वरूप, राज्य विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अधिक स्वायत्तता हासिल करने में सक्षम हो गए हैं, जिससे संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सका है।
- इसके अलावा, आयोग ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान में वृद्धि, विकेंद्रीकृत शासन और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को मजबूत करने की सिफारिश की। स्थानीय निकायों को सीधे धन आवंटित करके, राज्यों ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की अपनी क्षमता बढ़ाई है।
- इससे न केवल शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक नागरिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिला है।
- इसके अलावा, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों की राजस्व जुटाने की क्षमता को बढ़ाकर उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। केंद्रीय करों और अनटाइड फंड में अधिक हिस्सेदारी के साथ, राज्यों ने अपने राजस्व संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे केंद्रीय अनुदान पर उनकी निर्भरता कम हो गई है।
- इससे राज्यों को विकासात्मक पहल करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश करने और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने की अनुमति मिली है।

### चुनौतियां

- हालाँकि, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की है, लेकिन चुनौतियाँ और बाधाएँ बनी हुई हैं। राज्यों को संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और राजकोषीय घाटे से बचने के लिए राजकोषीय अनुशासन और विवेक बरतने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, बजट योजना, राजस्व प्रशासन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन सहित कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पहल की आवश्यकता है।

इस प्रकार, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी बढ़ाकर, निर्बाध अनुदान प्रदान करके और विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करके, आयोग ने राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा दिया है और राज्यों को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सशक्त बनाया है। हालाँकि, शेष चुनौतियों का समाधान करने और राज्यों में सतत विकास के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

## खतरनाक खेल: पतंजलि आयुर्वेद के दावों पर

व्यावसायिक हित को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए

- **ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट** का उल्लंघन करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया। ऐसा न करने के आश्वासन के बावजूद।
- पतंजलि के सह-संस्थापक बाबा रामदेव को भ्रामक विज्ञापनों के लिए अवमानना की कार्यवाही के साथ-साथ झूठी गवाही की कार्यवाही का भी सामना करना पड़ेगा।

- कोर्ट ने पतंजलि द्वारा कोरोनाल को कोविड-19 के इलाज के रूप में प्रचारित करने पर आंखें मूंदने के लिए सरकार की आलोचना की ।
- सरकार से झूठे दावों को अनुमति देने में मिलीभगत पर अपना रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया गया ।
- कोरोनाल और गैर-संचारी रोगों के इलाज सहित झूठे दावे करना जारी रखा ।
- कंपनी की अवज्ञा के कारण न्यायालय से अवमानना नोटिस मिला ।
- सरकार की ओर से निरोधक आदेशों की अनुपस्थिति ने पतंजलि के लिए मौन समर्थन का संदेह पैदा कर दिया ।
- स्वास्थ्य मामलों में पक्षपात खतरनाक हो सकता है, क्योंकि व्यावसायिक हित सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर हावी हो सकते हैं ।

## बेहतर भविष्य के लिए सिस्टम विज्ञान (निबंध)

भागों पर केंद्रित विशिष्ट विज्ञान के बजाय, एक उच्च स्तरीय विज्ञान की आवश्यकता है - समग्र, स्व-अनुकूली प्रणालियों में से एक

- प्यूरिसर्च सेंटर ने सत्तावादी शासकों बनाम बहुदलीय लोकतंत्र की प्राथमिकताओं को मापने के लिए 2023 में विभिन्न देशों में एक सर्वेक्षण किया ।
- सर्वेक्षण के नतीजों ने वैश्विक दक्षिण और पश्चिम दोनों में सत्तावादी शासकों के पक्ष में महत्वपूर्ण प्रतिशत दिखाया ।

सत्तावाद का तात्पर्य सरकार की एक ऐसी प्रणाली से है जो मजबूत केंद्रीय शक्ति और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता की विशेषता रखती है । ऐसी प्रणालियों में, सत्तारूढ़ प्राधिकरण राजनीतिक प्रक्रियाओं, नागरिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक प्रवचन पर सख्त नियंत्रण रखता है, अक्सर असहमति और विरोध को दबा देता है ।

उदाहरण: उत्तर कोरिया

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस में विपक्षी दलों को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है और राजनीतिक विरोधियों को उत्पीड़न और धमकी का शिकार होना पड़ता है ।

चीन में सरकार इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ा नियंत्रण रखती है

उदाहरण के लिए, सऊदी अरब में सार्वजनिक समारोहों और राजनीतिक सक्रियता को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है

- में, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों ने सत्तावादी शासकों के पक्ष में उच्च प्रतिशत प्रदर्शित किया, जिसमें भारत 85% था ।
- यहां तक कि पश्चिम में भी, यूनाइटेड किंगडम (37%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (32%) में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सत्तावादी शासकों को प्राथमिकता दी ।
- विश्व स्तर पर सरकारी आर्थिक नीतियों पर भरोसा कम हो गया है, जिससे बहुत अमीर और बाकी आबादी के बीच अंतर बढ़ गया है ।
- बड़े निगम और वित्तीय संस्थान सरकारों को उनके पक्ष में नीतियां बनाने के लिए प्रभावित कर रहे हैं, अक्सर श्रम अधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर ।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था और जनसंख्या की वृद्धि ने पर्यावरणीय संकटों को जन्म दिया है, जिसमें जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और पानी की कमी शामिल है।
- भारत, अत्यधिक आबादी होने के बावजूद, पर्यावरण प्रदर्शन में चुनौतियों का सामना करता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जैसे वैश्विक सूचकांकों में इसकी रैंकिंग खराब है।
- भारत में असमानता बढ़ रही है, जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय गिरावट हो रही है।

## सिस्टम का विज्ञान

- यह पाठ यह समझने के लिए कि दुनिया कैसे संचालित होती है, विभिन्न पहलुओं के अंतर्संबंध को समझने के महत्व पर जोर देती है।
- यह विज्ञान के संकीर्ण विशेषज्ञताओं में विखंडन की आलोचना करता है, जिससे अंतर-विषयक शिक्षा की कमी होती है।
- वैज्ञानिक अक्सर व्यापक निहितार्थों पर विचार किए बिना या अन्य विषयों से सीखे बिना अपने विशिष्ट क्षेत्रों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं।
- चिंता की बात यह है कि जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, विशेषज्ञ संकीर्ण विषयों के बारे में जानकार हो जाते हैं और बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज कर देते हैं।
- राजनीति और अर्थशास्त्र को जटिल सामाजिक प्रणालियों के अभिन्न घटकों के रूप में उजागर किया गया है, लेकिन उनकी बातचीत पूरी तरह से समझ में नहीं आती है।
- अर्थशास्त्र, जो दर्शन और मानविकी से रुभरा है, की सामाजिक कामकाज को समझने में असमर्थता के लिए आलोचना की जाती है, जो अक्सर मुक्त बाजार विचारधारों का पक्ष लेता है।
- चिकित्सा और जलवायु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता से विशिष्ट क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है लेकिन समाज पर व्यापक प्रभाव और प्रभाव को नज़रअंदाज किया जा सकता है।
- उच्च तकनीक समाधान जटिल प्रणालियों के भीतर विशिष्ट मुद्दों का समाधान कर सकते हैं लेकिन समाज के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर विचार नहीं कर सकता।
- पाठ से पता चलता है कि प्रकृति जैसी प्रणालियों से प्राप्त मानव बुद्धि, उन प्रणालियों को पूरी तरह से समझ या नियंत्रित नहीं कर सकती है।
- यह इस विश्वास की आलोचना करता है कि विज्ञान प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, चेतावनी देता है कि इस तरह का अहंकार मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालता है।
- अनिश्चितता के समय में, लोग उन नेताओं, धर्मगुरुओं और प्रौद्योगिकीविदों से निश्चितता की तलाश करते हैं जो ज्ञान और शक्ति होने का दावा करते हैं।
- पाठ उन नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डालता है जब नेता नीतियों को आकार देने के लिए सीमित समझ वाले अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हैं, जिससे लोगों और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है।
- यह दार्शनिक यशायाह बर्लिन के विचारकों को "हेजहोग" (एक बड़े विचार पर केंद्रित) और "लोमड़ियों" (कई चीजों के बारे में जानकार) में वर्गीकृत करने का संदर्भ देता है।
- जैसे महान लेखकों में हाथी और लोमड़ी दोनों के गुण होते हैं, जो अस्तित्व की जटिलता की सराहना करते हुए मौलिक सत्य को समझते हैं।
- विशिष्ट विज्ञान के बजाय, पाठ उच्च-स्तरीय विज्ञान की वकालत करता है जो मानव व्यवहार सहित समग्र, स्व-अनुकूली प्रणालियों पर विचार करता है।
- इस प्रस्तावित विज्ञान में तीन घटक शामिल होने चाहिए: सिस्टम अस्तित्व (विनम्रता), सिस्टम सोच (पैटर्न को पहचानना), और सिस्टम अभिनय।

## सहयोग के लिए उद्यम

- दुनिया को सभी के लिए बेहतर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठनों की आवश्यकता है।
- यह व्यापारिक निगमों और सेनाओं (लाभ और शक्ति) के उद्देश्यों को परिवारों (सदस्यों की भलाई) के उद्देश्यों से अलग करता है।
- परिवार सभी सदस्यों के लाभ के लिए लिंग और पीढ़ीगत क्षमताओं जैसे प्राकृतिक मतभेदों के बावजूद सहयोग का उदाहरण देते हैं।
- परिवार और सामाजिक कल्याण में महिलाओं के योगदान को अक्सर कम आंका जाता है और जीडीपी जैसे आर्थिक उपायों में यह प्रतिबिंबित नहीं होता है।
- जबकि अर्थशास्त्री कम महिला श्रम शक्ति भागीदारी पर प्रकाश डालते हैं, महिलाएं ऐतिहासिक रूप से अपने परिवारों और समुदायों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- पाठ अधिक देखभाल वाले दृष्टिकोण की ओर बदलाव की वकालत करता है, यह सुझाव देता है कि महिलाएं, प्राकृतिक परिवार निर्माता और सुविधाकर्ता के रूप में, इस बदलाव में योगदान दे सकती हैं।
- से परंपरागत रूप से पुरुषों के साथ जुड़े प्रतिस्पर्धी व्यवहार को अपनाने की अपेक्षा करने के बजाय महिलाओं की देखभाल के तरीकों से सीखना चाहिए।

## भारत में लिविंग विल्स (Living Wills) के कार्यान्वयन में देरी (GS PAPER II: गरिमा के साथ मरें)

राज्य सरकारें इसमें शामिल होने के लिए अनिच्छुक हैं; यह क्षेत्र जटिल है और इस पर चिकित्सा एवं कानूनी विशेषज्ञों के ध्यान की आवश्यकता है

- मार्च की शुरुआत में, केरल के त्रिशूर में 30 लोगों ने जीवित वसीयत निष्पादित की।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2018 से लिविंग वसीयत कानूनी हो गई है।
- यह निर्णय असाध्य रूप से बीमार रोगियों को इलाज रोकने या वापस लेने और सम्मानपूर्वक मरने की अनुमति देता है।
- लिविंग वसीयत मरीजों को उन स्थितियों के लिए चिकित्सा देखभाल विकल्प चुनने में सक्षम बनाती है जहां वे अपनी इच्छाओं को बता नहीं सकते हैं।
- कानूनी प्रावधान के बावजूद, भारत के अधिकांश हिस्सों में लिविंग वसीयत की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है।
- अधिकारी राज्य सरकारों के सीधे आदेश और मार्गदर्शन के बिना प्रक्रिया को लागू करने से झिझक रहे हैं।

## न्यायालय की प्रक्रिया

- प्रारंभ में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जीवित वसीयत को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और बोझिल थी।
- न्यायालय गुप्त उद्देश्यों वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंतित था।
- एक आवश्यकता यह थी कि जीवित वसीयत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना था, जो अव्यावहारिक साबित हुआ।

- परिणामस्वरूप, फैसले के बाद पहले पांच वर्षों में कुछ जीवित वसीयतें निष्पादित की गईं।
- जनवरी 2023 में, न्यायालय ने प्रक्रिया में खामियों को पहचाना और इसे और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए इसे सुव्यवस्थित किया।
- सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत, जीवित वसीयत पर दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष सत्यापित होना चाहिए।
- फिर उन्हें स्थानीय सरकार में एक "सक्षम अधिकारी" को सौंप दिया जाता है जो संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
- यदि रोगी असाध्य रूप से बीमार हो जाता है और निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, तो इलाज करने वाला डॉक्टर संरक्षक या डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के पास मौजूद प्रति के आधार पर जीवित वसीयत को प्रमाणित कर सकता है।
- हालाँकि, अधिकांश स्थानीय सरकारों ने जीवित वसीयत के लिए संरक्षकों को नामित नहीं किया है, और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए अभी तक कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं है।
- उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में संरक्षकों की नियुक्ति के लिए बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।
- लिविंग विल बनाने के बावजूद इसके क्रियान्वयन की गारंटी नहीं है।
- दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उपचार रोकने या वापस लेने के निर्णय को प्राथमिक मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और माध्यमिक मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- माध्यमिक बोर्ड को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित डॉक्टर की आवश्यकता होती है, जिससे यह अस्पताल के बुनियादी ढांचे पर निर्भर हो जाता है।
- इस सेटअप का मतलब है कि असाध्य रूप से बीमार मरीज़ महत्वपूर्ण चिकित्सा निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, भले ही उनके पास जीवित रहने की इच्छा हो।
- अधिकारी, कई व्यक्तियों की तरह, मृत्यु और जीवन के अंत की देखभाल जैसे विषयों पर असहज महसूस करते हैं, जो कार्यान्वयन चुनौतियों में योगदान करते हैं।
- दिशा-निर्देशों में अस्पष्टताएं और "निकटतम रिश्तेदार" जैसी स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव, निर्णय लेने को और अधिक जटिल बना देता है।
- परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद चिकित्सा देखभाल संबंधी निर्णयों में स्पष्ट कानूनी समाधान का अभाव है।
- अधिकारी वरिष्ठों के स्पष्ट निर्देशों और राज्य सरकार द्वारा स्थापित विस्तृत प्रक्रियाओं के बिना कार्य करने में संकोच करते हैं।
- वे विवेक का प्रयोग करने के बजाय निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिए विशिष्ट आदेशों और प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देते हैं।

## राज्यों के लिए आगे की राह

- राज्य सरकारें जीवित वसीयत को लागू करने की जटिलताओं को संबोधित करने में झिझक रही हैं, जिसके लिए चिकित्सा और कानूनी पेशेवरों की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- जबकि हरियाणा ने सिविल सर्जनों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए, लेकिन कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन या प्रोटोकॉल प्रदान नहीं किया।
- इसके विपरीत, ओडिशा फैसले को लागू करने के लिए विस्तृत मसौदा आदेश विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर अधिक गहन दृष्टिकोण अपना रहा है।
- आशा है कि अधिक राज्य ओडिशा के दृष्टिकोण का अनुकरण करेंगे।

- फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार मॉडल आदेश और प्रोटोकॉल बनाकर और प्रकाशित करके मदद कर सकती है।
- गरिमा के साथ मरने के अधिकार की पुष्टि करने वाले सुप्रीम कोर्ट के छह साल पहले के फैसले के बावजूद, सरकारों ने अभी तक इसे अधिनियमित करने के लिए बुनियादी कदम नहीं उठाए हैं।
- कार्यान्वयन के बिना, डॉक्टर मरीजों की इच्छाओं का सम्मान करने के कानूनी निहितार्थों के बारे में चिंतित रहते हैं, जैसा कि गहन देखभाल डॉक्टरों के 2023 सर्वेक्षण से पता चला है।
- प्रभावी मार्गदर्शन एवं सतत कार्यवाही सरकार के सभी स्तरों से डॉक्टरों को मरीजों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है।

## भारत झींगा फार्मों में अपमानजनक स्थितियों के आरोपों को खारिज करता है

वैश्विक मानदंडों के अनुपालन में सभी निर्यात शिपमेंट का दावा करता है; अमेरिकी मानवाधिकार समूह की रिपोर्ट अमेरिकी झींगा बाजार में भारत के नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने के लिए 'निहित स्वार्थों' से प्रेरित प्रतीत होती है

- कुल \$8.09 बिलियन या ₹64,000 करोड़ के समुद्री खाद्य निर्यात के साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को झींगा का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
- भारत के कुल समुद्री भोजन निर्यात में झींगा निर्यात का योगदान एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो \$5.6 बिलियन तक पहुंच गया।
- अमेरिकी झींगा बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2022-23 में 21% से बढ़कर 40% हो गई है और इसने थाईलैंड, चीन, वियतनाम और इकाडोर जैसे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है।
- शिकागो स्थित मानवाधिकार समूह द्वारा उठाए गए मानवाधिकारों और पर्यावरण के दुरुपयोग के आरोपों को संबोधित करने के लिए समुद्री भोजन निर्यातकों से मिलेंगे।
- कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी लैब (सीएएल) की एक रिपोर्ट में उल्लिखित आरोप, झींगा हैचरी, बढ़ते तालाबों और छीलने वाले शेडों में काम करने की स्थितियों पर केंद्रित हैं।
- एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भारत की झींगा निर्यात मूल्य श्रृंखला समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा प्रमाणित है, जो मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- अधिकारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और सुझाव दिया कि वे वैश्विक बाजारों में भारत के जलीय कृषि क्षेत्र की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से निहित स्वार्थों से प्रेरित हो सकते हैं।
- आंध्र प्रदेश में लगभग 100,000 झींगा फार्म हैं, जो भारत के कुल झींगा उत्पादन में लगभग 70% का योगदान करते हैं।
- झींगा क्षेत्र में लगभग 8 मिलियन नौकरियों में से लगभग 70% महिलाएं हैं, जिनमें से लगभग 200,000 हैचरी और जलीय कृषि फार्मों में कार्यरत हैं और शेष प्रसंस्करण और फ्रीजिंग इकाइयों में कार्यरत हैं।
- मंत्रालय का लक्ष्य 2025-26 तक समुद्री खाद्य निर्यात को ₹1 लाख करोड़ तक बढ़ाना है और निर्यातकों को अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में चिंताओं को दूर करने के लिए झींगा फार्मों में काम करने की स्थिति पर स्वतंत्र अध्ययन करने की सलाह दे सकता है।

- मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से सीएएल रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने का आग्रह किया है, खासकर असुरक्षित और अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करने वाले श्रमिकों के संबंध में।
- एक अधिकारी ने सीएएल रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह चुनिंदा घटनाओं को उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना उजागर करती है और भारत के झींगा पालन और प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रथाओं को गलत तरीके से सामान्यीकृत करती है।
- अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में नियामक एजेंसियां नियमित रूप से झींगा मूल्य श्रृंखला की निगरानी करती हैं, और यूएसएफडीए, यूरोपीय आयोग और चीन की जीएसी जैसी संस्थाओं द्वारा ऑडिट अंतरराष्ट्रीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

## कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन सीनेट अध्यक्ष बने

यह पद हुन सेन को राजा के विदेश में होने पर राज्य के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।

- पूर्व कंबोडियन नेता हुन सेन को सीनेट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण औपचारिक भूमिका है।
- हुन सेन ने लगभग चार दशकों तक कंबोडिया पर कठोर शासन करने के बाद अगस्त में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सत्ता अपने बेटे हुन मैनेट को सौंप दी।
- उनकी सत्तारूढ़ कंबोडियन पीपुल्स पार्टी (सीपीपी) महत्वपूर्ण विपक्षी दलों के बिना हुए राष्ट्रीय चुनावों में भारी जीत हासिल की।
- फरवरी में, सीपीपी ने सीनेट चुनाव में 58 में से 55 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी खमेर विल पार्टी ने शेष सीटें हासिल कीं।
- राजा नोरोडोम सिहामोनी द्वारा बुलाई गई पहली बैठक के दौरान सीनेटरों ने सर्वसम्मति से हुन सेन को सीनेट के अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी।
- यह पद हुन सेन को राजा के विदेश में होने पर राज्य के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।
- हुन सेन ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और कंबोडिया की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक भूमिका का उपयोग करने का अपना इरादा बताया।
- कुल 62 सीनेटर हैं, जिनमें से 58 फरवरी में चुने गए और दो क्रमशः राजा और नेशनल असेंबली द्वारा नियुक्त किए गए।
- विश्लेषकों का मानना है कि हुन सेन की नई भूमिका उन्हें देश में प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम बनाएगी, क्योंकि सीनेट राष्ट्र के राजनीतिक प्रतीक के रूप में सर्वोच्च औपचारिक भूमिका रखती है।
- नियुक्ति को प्रतीकात्मक माना जा रहा है, विशेषकर राजा की लगातार यात्राओं के कारण।
- हुन सेन के प्रशासन में उनके कई रिश्तेदार शामिल हैं, जो सरकार भर में सत्ता के एकीकरण का संकेत देते हैं।
- आलोचक हुन सेन के शासन के दौरान पर्यावरण विनाश, भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के दमन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं।

### प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: जब कोई राज्य सरकार भारत के भीतर उधार लेती है तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा के रूप में किया जाता है?

- (ए) भारत की समेकित निधि
- (बी) राज्य की समेकित निधि
- (सी) भारतीय रिजर्व बैंक जमा
- (डी) भारत का सार्वजनिक खाता

प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत भारत सरकार की भूमिका का सटीक वर्णन करता है?

- (ए) यह राज्य सरकारों के लिए उधार सीमा निर्धारित करता है।
- (बी) यह राज्यों को धन उधार दे सकता है या राज्य ऋण की गारंटी दे सकता है।
- (सी) राज्य सरकारों की उधार प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं है।
- (डी) यह राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए सभी ऋणों को मंजूरी देता है।

प्रश्न 3: भारतीय संविधान में अनुच्छेद 293 के प्राथमिक उद्देश्य को पहचानें:

- (ए) राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना
- (बी) राज्यों को अत्यधिक ऋण जमा करने से रोकना।
- (सी) राज्य के वित्त पर केंद्र सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित करना।
- (डी) सुचारू अंतर-राज्य वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए।

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा मूल FRBM अधिनियम (2003) का प्राथमिक उद्देश्य था?

- (ए) राजस्व घाटे को खत्म करना और राजकोषीय घाटे को कम करना
- (बी) एक विशिष्ट ऋण-से-जीडीपी अनुपात बनाए रखना
- (सी) पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाना
- (डी) प्राथमिक घाटे को खत्म करना

प्रश्न 5: 2018 में FRBM संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या पेश किया गया था?

- (ए) राजकोषीय घाटे का पूर्ण उन्मूलन
- (बी) ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर ध्यान केंद्रित करना
- (सी) राज्य सरकारों द्वारा किसी भी उधार पर सख्त प्रतिबंध
- (डी) मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का परिचय

प्रश्न 6: द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) कौन प्रकाशित करता है?

- (ए) विश्व आर्थिक मंच, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में
- (बी) विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के सहयोग से
- (सी) प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन)
- (डी) विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)

प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नीतिगत उद्देश्यों में से एक नहीं है जिसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) ट्रैक करना चाहता है?

- (ए) जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन
- (बी) पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति
- (सी) पर्यावरणीय स्वास्थ्य

(डी) व्यापार समझौते और शुल्क

प्रश्न 8: पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) विभिन्न पर्यावरणीय संकेतकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंक करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईपीआई में विचार की जाने वाली मुद्दा श्रेणियों में से एक है?

- (ए) जैव विविधता  
(बी) वायु गुणवत्ता  
(सी) जल संसाधन  
(D) उपरोक्त सभी

प्रश्न 9: 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में कौन सा देश अंतिम स्थान पर था?

- (ए) चीन  
(बी) भारत  
(सी) संयुक्त राज्य अमेरिका  
(डी) ब्राजील

### प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

सवाल	उत्तर और स्पष्टीकरण
<p>प्रश्न 1: जब कोई राज्य सरकार भारत के भीतर उधार लेती है तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा के रूप में किया जाता है?</p> <p>(ए) भारत की समेकित निधि (बी) राज्य की समेकित निधि (सी) भारतीय रिजर्व बैंक जमा (डी) भारत का सार्वजनिक खाता</p>	<p>उत्तर: (बी) राज्य की संचित निधि</p> <p>स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 293 में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा उधार लिया गया धन उस विशेष राज्य की समेकित निधि के विरुद्ध सुरक्षित है।</p>
<p>प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत भारत सरकार की भूमिका का सटीक वर्णन करता है?</p> <p>(ए) यह राज्य सरकारों के लिए उधार सीमा निर्धारित करता है। (बी) यह राज्यों को धन उधार दे सकता है या राज्य ऋण की गारंटी दे सकता है। (सी) राज्य सरकारों की उधार प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं है। (डी) यह राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए सभी ऋणों को मंजूरी देता है</p>	<p>उत्तर: (बी) यह राज्यों को धन उधार दे सकता है या राज्य ऋण की गारंटी दे सकता है।</p> <p>स्पष्टीकरण: भारत सरकार संसद द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के तहत राज्यों को ऋण दे सकती है या उनके ऋणों के लिए गारंटी प्रदान कर सकती है।</p>
<p>प्रश्न 3: भारतीय संविधान में अनुच्छेद 293 के प्राथमिक उद्देश्य को पहचानें:</p> <p>(ए) राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना (बी) राज्यों को अत्यधिक ऋण जमा करने से रोकना। (सी) राज्य के वित्त पर केंद्र सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित करना।</p>	<p>उत्तर: (बी) राज्यों को अत्यधिक ऋण जमा करने से रोकने के लिए।</p> <p>स्पष्टीकरण: जबकि अनुच्छेद 293 राजकोषीय संघवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के पहलुओं को छूता है, इसका मुख्य उद्देश्य अस्थिर ऋण को रोकने के लिए राज्य उधार पर जांच शुरू करना है।</p>

<p>(डी) सुचारू अंतर-राज्य वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए।</p>	
<p>प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा मूल FRBM अधिनियम (2003) का प्राथमिक उद्देश्य था?  (ए) राजस्व घाटे को खत्म करना और राजकोषीय घाटे को कम करना  (बी) एक विशिष्ट ऋण-से-जीडीपी अनुपात बनाए रखना  (सी) पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाना  (डी) प्राथमिक घाटे को खत्म करना</p>	<p>उत्तर: (ए) राजस्व घाटे को खत्म करना और राजकोषीय घाटे को कम करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>राजस्व घाटा दूर करना:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। यह दर्शाता है कि सरकार अनिवार्य रूप से मौजूदा खर्चों को पूरा करने के लिए उधार का सहारा लेकर अपनी क्षमता से परे जीवन यापन कर रही है।</li> <li>○ राजस्व घाटे को खत्म करना एफआरबीएम अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित करना था कि सरकार राजस्व का उपयोग केवल अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए करती है, न कि परिसंपत्ति निर्माण के वित्तपोषण के लिए।</li> </ul> </li> <li>• <b>राजकोषीय घाटा कम करना:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय (राजस्व और पूंजी दोनों) और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।</li> <li>○ एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करना है - इसे पूरी तरह खत्म नहीं करना है - उधार पर निर्भरता कम करना और स्वस्थ राजकोषीय संतुलन बनाए रखना है।</li> </ul> </li> <li>• <b>एक विशिष्ट ऋण-से-जीडीपी अनुपात बनाए रखना (विकल्प बी):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ जबकि एफआरबीएम अधिनियम ने जिम्मेदार ऋण प्रबंधन के महत्व को स्वीकार किया, इसमें विशिष्ट ऋण-से-जीडीपी अनुपात के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था।</li> </ul> </li> <li>• <b>पूंजीगत व्यय को जीडीपी के एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाना (विकल्प सी):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ एफआरबीएम अधिनियम ने बुनियादी ढांचे और अन्य दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित किया, लेकिन इसमें जीडीपी का एक विशिष्ट प्रतिशत आवंटित करने की बाध्यता नहीं थी।</li> </ul> </li> <li>• <b>प्राथमिक घाटा दूर करना (विकल्प डी):</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान है। एफआरबीएम अधिनियम ने राजकोषीय घाटे में कमी का लक्ष्य रखा, जिसका परिणामी प्रभाव प्राथमिक घाटे पर भी पड़ेगा, लेकिन प्राथमिक घाटे को खत्म करना इसका एकमात्र फोकस नहीं था।</li> </ul> <p><b>विकल्प (ए) प्राथमिक उद्देश्य क्यों है?</b>  एफआरबीएम अधिनियम, संक्षेप में, राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने का प्रयास करता है। राजस्व घाटे को खत्म करने और राजकोषीय घाटे को कम करने के इसके प्राथमिक लक्ष्य सीधे तौर पर यह सुनिश्चित करने के अनुरूप हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>सतत सार्वजनिक वित्त:</b> उच्च राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा सरकारी वित्त को ऋण संचय और अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।</li> <li>2. <b>अंतर-पीढ़ीगत इकिटी:</b> वर्तमान उपभोग को निधि देने के लिए अत्यधिक उधार लेने से भावी पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ पड़ता है।</li> <li>3. <b>व्यापक आर्थिक स्थिरता:</b> बड़े घाटे से मुद्रास्फीति का दबाव पैदा हो सकता है और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।</li> </ol>
<p>प्रश्न:6 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था:</p> <p>(ए) 1998  (बी) 2000  (सी) 2003  (डी) 2008</p>	<p>उत्तर: (सी) 2003</p> <p>स्पष्टीकरण: FRBM अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था।</p>
<p>प्रश्न:7 निम्नलिखित में से क्या 2018 में FRBM संशोधन द्वारा पेश किया गया था?</p> <p>(ए) राजकोषीय घाटे का पूर्ण उन्मूलन  (बी) ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर ध्यान केंद्रित करना  (सी) राज्य सरकारों द्वारा किसी भी उधार पर सख्त प्रतिबंध  (डी) मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण ढांचे का परिचय</p>	<p>उत्तर: (बी) ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर ध्यान केंद्रित करना</p> <p>स्पष्टीकरण: 2018 एफआरबीएम संशोधन ने भारत के ऋण बोझ को कम करने पर अधिक जोर दिया।</p>
<p>प्रश्न:8 एफआरबीएम ढांचे के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?</p> <p>(ए) यह राज्यों के लिए किसी भी प्रावधान के बिना केंद्र सरकार पर केंद्रित है।  (बी) केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए ऋण लक्ष्य निर्धारित करती है।  (सी) एफआरबीएम अधिनियम में विशेष परिस्थितियों के दौरान लचीलेपन का कोई प्रावधान नहीं है।</p>	<p>उत्तर: (बी) केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए ऋण लक्ष्य निर्धारित करती है।</p> <p>स्पष्टीकरण: एफआरबीएम ढांचे और इसके संशोधनों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए ऋण लक्ष्य निर्धारित करने के प्रावधान शामिल हैं।</p>

<p>(डी) 2018 में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों लक्ष्य हटा दिए गए।</p>	
<p>प्रश्न:9 द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) कौन प्रकाशित करता है?  (ए) विश्व आर्थिक मंच, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में  (बी) विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के सहयोग से  (सी) प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन)  (डी) विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)</p>	<p>उत्तर: (ए) विश्व आर्थिक मंच, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में</p> <p>स्पष्टीकरण: ईपीआई विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है।</p>
<p>प्रश्न:10 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नीतिगत उद्देश्यों में से एक नहीं है जिसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) ट्रैक करना चाहता है?  (ए) जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन  (बी) पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति  (सी) पर्यावरणीय स्वास्थ्य  (डी) व्यापार समझौते और शुल्क</p>	<p>उत्तर: (डी) व्यापार समझौते और टैरिफ</p> <p>स्पष्टीकरण: जबकि आर्थिक कारक पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, ईपीआई मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य प्रभावों से संबंधित पर्यावरणीय संकेतकों पर केंद्रित है।</p>
<p>प्रश्न:11 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) विभिन्न पर्यावरणीय संकेतकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंक करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईपीआई में विचार की जाने वाली मुद्दा श्रेणियों में से एक है?  (ए) जैव विविधता  (बी) वायु गुणवत्ता  (सी) जल संसाधन  (डी) उपरोक्त सभी</p>	<p>उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी</p> <p>स्पष्टीकरण: ईपीआई जैव विविधता, वायु गुणवत्ता, जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन और अन्य सहित कई मुद्दा श्रेणियों में संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करता है।</p>
<p>प्रश्न:12 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में कौन सा देश अंतिम स्थान पर था?  (ए) चीन  (बी) भारत  (सी) संयुक्त राज्य अमेरिका  (डी) ब्राजील</p>	<p>उत्तर: (बी) भारत</p> <p>स्पष्टीकरण: भारत को 2022 ईपीआई में सबसे निचले स्थान पर रखा गया, जिससे इसके पर्यावरणीय प्रदर्शन पर चर्चा और बहस हुई।</p>
<p>प्रश्न 13: अनुच्छेद 293 के तहत, कोई राज्य सरकार किसकी सहमति के बिना भारत के बाहर ऋण नहीं ले सकती:  (ए) भारतीय रिजर्व बैंक  (बी) भारत के राष्ट्रपति  (सी) भारत सरकार  (डी) राज्य विधानमंडल</p>	<p>उत्तर: (सी) भारत सरकार</p> <p>स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 293 निर्दिष्ट करता है कि कोई राज्य केंद्र सरकार (भारत सरकार) की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं उठा सकता है यदि उसके पास पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा बकाया ऋण या गारंटी है।</p>